इरेडा ने बोली जमा करने की तिथि 15 जून तक बढ़ाई

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा), जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के तहत एक पीएसयू है, ने वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के साथ 12,000 मेगावाट तक की ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) स्कीम फेज- II के कार्यान्वयन हेतु बोली जमा करने की अवधि को 15 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले बोली जमा करने की अंतिम तारीख 30 मई थी। वीजीएफ, घरेलू और आयातित सौर सेल और मॉड्यूल के बीच लागत अंतर को कवर करने के लिए प्रदान किया जाता है। वीजीएफ दो चरणों (अंश) में जारी किया जाएगा।

सीपीएसयू को 15 जून 2021 तक अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी और सफल बोलीदाताओं का चयन 20 जुलाई तक किया जाना है। इससे पहले, एमएनआरई ने इस स्कीम के लिए इरेडा को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया था।

इस स्कीम के तहत, सरकारी उत्पादकों द्वारा उत्पादित बिजली का उपयोग पारस्परिक रूप से सहमत उपयोग शुल्क के भुगतान पर 2.45 रुपये/यूनिट से अधिक नहीं पर स्वयं-उपयोग या सरकारी /सरकारी संस्थाओं, या तो सीधे या डिस्कॉम्स के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। अधिकतम अनुमत वीजीएफ 55 लाख रुपये प्रति मेगावाट है। सरकारी निर्माता को वास्तविक वीजीएफ परियोजना डेवलपर का चयन करने के लिए बोली पैरामीटर के रूप में वीजीएफ राशि का उपयोग करके बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय किया जाएगा।

अधिकतम अनुमत वीजीएफ राशि की समय-समय पर एमएनआरई द्वारा समीक्षा की जाएगी और यदि लागत में अंतर कम हो जाता है तो इसे कम कर दिया जाएगा।

वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सोलर पीवी की स्थापना करने की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए केंद्र सरकार के लक्ष्य के हिस्से के रूप में, इरेडा ने इस वर्ष 29 जनवरी को देश में कहीं पर भी ग्रिड (मिनी और माइक्रो ग्रिड सहित) कनेक्टेड सोलर पीवी परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। यह फेज -II (अंश -III) के तहत 5,000 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए "बिल्ड ओन ऑपरेट" (बी-ओ-ओ) के आधार पर किया जाना है।